

65व अखिल भारतीय सहकारो सप्ताह
के अवसर पर
माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
श्री राधामोहन सिंह
का सम्बोधन

भारतीय राष्ट्रीय सहकारो संघ के 65 व अखिल भारतीय सहकारो सप्ताह के अवसर पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह अत्यंत हष का विषय है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारो संघ को ओर से 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक 65 व अखिल भारतीय सहकारो सप्ताह का अयोजन किया जा रहा है। सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश म सहकारो आंदोलन के प्रति लोगों म रुझान पैदा होगा। अच्छा बात है कि इस दौरान सहकारिताओं को सफलता और उपलब्धियाँ का उल्लेख हो रहा है। सहकारिता के विषय म लोगों म जागरूकता फैलाने का यह एक अच्छा अवसर है। सहकारिताओं को अपने काय का आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा। इससे आने वाली चुनौतियाँ का डटकर मुकाबला करने का उपाय निकलेगा। सहकारो नेतृत्व पर पारदर्शिता अपनाने का जोर बढ रहा है। संभव है कि ऐसे आयोजना से सहकारो नेतृत्व म पारदर्शिता बढेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वष 2022 तक किसानों को आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सहकारिता को मजबूती से इस लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने म मदद मिलेगी। सहकारिताएं इस पुनीत यज्ञ म सक्रिय योगदान कर रही ह। यह प्रसन्नता को बात है। भारत गाँवों का देश है। शहर चाहे जितना चकाचाँधपूण लगे लेकिन आज भी गाँवों म जीवन है। लोगों म आपसी सरोकार है। सहकारिता का जनसरोकार और किसानों से सीधा संबंध है। इस लिहाज से इस वष सहकारिता सप्ताह के विषय का खास महत्व है। विषय है “ग्रामीण समृद्धि के लिए सहकारिताओं के माध्यम से समावेशी विकास और सुशासन” ।

राष्ट्र निमाण म सहकारिताओं के योगदान का मजबूत इतिहास है। सहकारिताएं समाज के गरोब और निम्न वग के लोगों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रही हैं। सहकारो संस्थाओं ने विकास के लाभों के समाज के सबसे निम्न वग के लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। यह

समाज के अमीर और गरीब तबके के मध्य एक सशक्त पुल का काम करती है। यह सच है कि सहकारिताओं को ओर से किए जा रहे अच्छे कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। निश्चित ही इसके चलते गरीबों को आर्थिक स्थिति में समृद्धि आई है जो समावेशी विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। इन सफलताओं को वजह से ही केंद्र सरकार को सहकारिताओं से बड़ी अपेक्षा है।

सहकारिताएं प्रजातांत्रिक मूल्य पर आधारित हैं। इसमें आम और खास का भेद नहीं होता है। जनता के हित से जुड़ी संस्थाएं हैं। यह सदस्यों का ध्यान रखती हैं। निजी उद्यमियों को तरह केवल लाभ पर इनका ध्यान केन्द्रित नहीं रहता है। ये बात सिर्फ किताबी नहीं रहनी चाहिए। बल्कि यह हमेशा ख्याल रहना चाहिए कि समाज और समुदाय के प्रति सहकारिताओं का दायित्व बढ़ा है। भारत में 8 लाख से ज्यादा सहकारिताएं हैं। भारत का सहकारी आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। उर्वरक वितरण, चीनी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सहकारी साख, हथकरघा इत्यादि क्षेत्रों में सहकारिताओं ने विगत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

सहकारिताएं स्वरोजगार का सर्वोत्तम माध्यम हैं तथा मत्स्य, श्रम, हथकरघा और महिला सहकारिताओं ने समाज के निम्न वर्ग को समाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुग्ध सहकारिताओं ने श्वेत क्रान्ति द्वारा भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है। आवास सहकारिताओं ने समाज के कमजोर वर्ग को कम दाम पर आवास की सुविधाएं प्रदान की हैं। कुल मिलाकर समावेशी विकास में सहकारिताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह देखा गया है कि सहकारिताओं के विस्तृत विकास के बावजूद अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पा रही है। ये सफल व्यावसायी इकाइयों के रूप में उभरकर नहीं आ पाई हैं। भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता, वैद्यनाथ कमेटी की सिफारिशों का कार्यान्वयन, आदि ऐसे कदम हैं जिनके तहत न केवल सहकारिताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया गया है, बल्कि उन्हें सदस्यों की सहभागिता पर केन्द्रित कर उनके प्रजातांत्रिक स्वरूप को मजबूत करने का भी प्रयास किया गया है।

एन.सी.डी.सी के माध्यम से सरकार विभिन्न गतिविधियों जैसे:- हस्तकरघा, ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि क्षेत्रों में राज्यों को सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। पूर्वोक्त राज्यों को सहकारी आंदोलन को वित्तीय सहायता द्वारा मजबूत करने के लिए हाल में सरकार ने कई

महत्वपूर्ण कदम उठाए है। सरकार वित्तीय सहायता द्वारा प्रार्थमिक सहकारो समितियों को सशक्त करने और उन्हें कोर बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है ताकि वे पूर्णतः कम्प्यूटरीयुक्त होकर गरीबों को बिना व्यवधान के साख मुहैया करा सक।

भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का गरीबी से देश को उबारने पर विशेष जोर है। उनके नेतृत्व म भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुरुआत का है। जैसे जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मेक इन इण्डिया, सोशल हेल्थ काड स्कोम इत्यादि। इन सब स्कोमों के कार्यान्वयन म सहकारिताओं का विशाल और विस्तृत नेटवर्क बहुत काम आ सकता है। सहकारिताओं को इन सब स्कोमों म अच्छा भागीदारों के लिए एक सशक्त नीति बनानी होगी ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। कौशल विकास योजना म सहकारिताएं रोजगार-सृजन के क्षेत्र म अच्छा योगदान दे सकती है, क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारों को दूर करने के लिए सहकारिता सशक्त माध्यम है।

बदलते परिवेश म सहकारिताओं को प्रौद्योगिकी का नई तकनीकों को अपनाना होगा। कई सहकारो संस्थाओं जैसे अमूल, इफको, कृभको, सारस्वत बैंक इत्यादि ने नई तकनीक को अपनाकर काफी अच्छा प्रगति का है, जो दूसरो सहकारो संस्थाओं के लिए अच्छा उदाहरण है। विमुद्रीकरण के दौरान कुछ सहकारो संस्थाओं जिसमें शहरी साख सहकारी बैंक प्रमुख हैं, ने इसके कार्यान्वयन म अच्छा भूमिका निभाई है। कैशलेस व्यवस्था को अपनाने म भी सहकारिताओं ने महत्वपूर्ण कदम उठाएं है, पर इस दिशा म आगे बढ़ने के लिए सहकारिताओं को और भी प्रयास करने का जरूरत है।

सहकारो शिक्षण और प्रशिक्षण का सहकारिताओं को मजबूत करने म बड़ी भूमिका है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यथायोग्य वित्तीय सहायता प्रदान का है, और आगे भी करती रहेगी। इनके कार्यक्रमों का गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब लोगों तक पहुंचाने का आवश्यकता है। युवाओं और स्कूलों बच्चों को सहकारो प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारो संघ ने विगत कुछ वर्षों म अच्छे प्रयास किए है। उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, इसका म आश्वासन देता हूँ।

देश का आधी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। 50 सालों का स्वतंत्रता के बाद हमारे किसान अभी भी निधन, अशिक्षित और कमजोर है। वे अभी भी सामान्य जरूरत का वस्तुओं से वंचित है। सहकारिताओं के माध्यम से इन किसानों म सहकारो जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है ताकि वे

ज्यादा से ज्यादा सहकारी संस्थाओं से जुड़ सक। सहकारी सप्ताह के कार्यक्रमों में इस विषय पर आवश्यक चर्चा होगी। किसानों को आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

आज जब सहकारी संस्थाओं को निजी उद्यमों से चुनौतियाँ का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मेरा मानना है कि सहकारी पदाध्यक्षों में गुणवत्ता, पैकेजिंग, स्टोरेज, विपणन जैसे क्षेत्रों में काफी बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए सहकारिताओं को अपनी नीतियों में समय की माँग को देखते हुए बदलाव लाना होगा।

सहकारी सप्ताह का आयोजन एक महज औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस दौरान सहकारिताओं को युवा वर्ग तक पहुँचाने की हर कोशिश करनी चाहिए ताकि वे सहकारी आंदोलन की खूबियाँ और विभिन्न सफलताओं की कहानियाँ से अवगत हों। डिजिटल मीडिया का उपयोग सहकारी संस्थाएँ इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा कर सकती हैं, ताकि सहकारी आंदोलन का खूब प्रचार-प्रसार हो सके। सहकारी आंदोलन के दौरान सहकारी आंदोलन की विभिन्न सफलताओं की कहानियाँ को प्रकाश में लाना होगा और जन-जन तक पहुँचाना होगा।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की आय को सन् 2022 तक दोगुना करने हेतु कृत संकल्प हैं। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहकारिताएँ काफी सक्षम हैं, लेकिन इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें नई-नई रणनीतियों को अपनाना होगा, और दूरदृष्टि से विभिन्न नीतियों का कार्यान्वयन करना होगा। सहकारिताओं के लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर है कि वे इस मौके का पूरा फायदा उठाएँ और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ें। मेरा निजी तौर पर मानना है कि देश की सहकारी नेतृत्व अगर इमानदार और पारदर्शी हो जाए। और फिर ठान ले कि भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना देनी है, तो यह काम आसान हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सतत विकास के लिए यूनाइटेड नेशन्स 2030 एजेंडा में सहकारिता से बड़ी भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। भारतीय सहकारी आंदोलन विश्व के लिए सतत विकास का एक बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत करता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस दिशा में भारतीय सहकारी आंदोलन महत्वपूर्ण पहल करेगा।

अंत में अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह की सफलता की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आयोजनों के जरिए आने वाले दिनों में सहकारिताएँ हमारे समाने मौजूद विकास की तमाम चुनौतियों का समाधान बनकर आएंगी।